प्रौद्योगिकी का संस्थागत विकास/उन्नयन, सहयोगी संस्थाओं से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी-सहयोग संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर करना और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के सहयोग से प्रौद्योगिकी का विकास/उन्नयन करना इत्यादि शामिल हैं। चूंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का कार्यनिष्पादन विभिन्न तत्वों, जैसे संयंत्र और मशीनरी की दशा, बिजली और कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार मांग/क्रय आदेश की स्थिति इत्यादि पर निर्भर करता है इसलिये केवल प्रौद्योगिकी उन्नयन से प्राप्त किए लाभों की गणना करना आसानी से संभव नहीं है। बहरहाल पिछले तीन वर्षों तक की अवधि की जानकारी उपलब्ध हैं और उसके दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में क्षमता का उपयोग निम्न प्रकार से है :

विवरण	1991–92 (%)	1990–91 (%)	1989–90 (%)
जिन एककों ने 75% से अधिक क्षमता का उपयोग दर्ज किया है उनकी प्रतिशतता	56	54	53
जिन एककों ने 50% या उससे अधिक और 75% से कम क्षमता का उपयोग दर्ज किया है उनकी प्रतिशतता	20	26	23
जिन एककों ने 50% से कम क्षमता का उपयोग दर्ज किया है उनकी प्रतिशतता	24	20	24
कुल	100	100	100

मारुति उद्योग लिमिटेड में अनियमितताएं

3227. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मारुति उद्योग लिमिटेड में कथित अनियमितताओं की जांच करने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) अब तक मारुति उद्योग लिमिटेड में कुल कितनी धनराशि का घपला हुआ है तथा इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने जांच के आदेश दे दिये हैं ; यदि नहीं, तो ऐसे आदेशों के कब तक दिये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

Appointment of Directors in PSUs

3228. SHRI GHUFRAN AZAM :
PROF. SAURIN BHATTACHARAYA :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state : (a) whether there has been excessive delays in granting approvals of the Government to the appointments of Directors in Public Sector Undertakings ;

(b) whether the selected candidates for the various posts of Board level appointments as were done by the PESB in the first four months of the year 1993 are yet to get clearance ;

(c) whether the concerned ministries have been withholding information from the ACC ; and

(d) if so, the facts thereof and steps to be taken to expedite the approvals ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Committee on KVIC

3229. SHRI S. MUTHU MANI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are planning to set up a committee to get into the problems being faced by the Khadi and Village Industries ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) how many applications/proposals are pending for clearance from Government to set up projects under this category in Tamil Nadu ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) and (b) The Government have already constituted a High Power Committee headed by the Prime Minister with a view to accelerate the growth & development of Khadi & Village industries sector.

(c) Information is being collected and will be laid on the table of the House.